

14.46 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377**(i) NEED FOR UNDERGROUND SURVEY IN CHHATTISGARH AREA OF MADHYA PRADESH.**

श्री कैम्प्यूर भूखण्ड (रायपुर) : मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस्पात तथा खान, ऊर्जा एवं योजना भविक्षण का व्यापार देश के मध्य भाग तथा मध्य प्रदेश के दक्षिण एवं पूर्वी घंटल जिले छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, के अववेशी भूवेक्षण तथा भू-सर्वेक्षण की ओर दिलाना चाहता हूँ। व्यापार रहे कि यह क्षेत्र अकूत खनिज सम्पद स्वप्ने गर्भ में समेटे हुए है। कहीं-कहीं रेडियो सक्रियता भी पाई गई है, जिस से यूरेनियम खनिज बड़ी मात्रा में पाये जाने की संभावना है। इस के अतिरिक्त प्रन्य बहुमूल्य खनिज मिलने की संभावनाओं से दंकार नहीं किया जा सकता। बस्तर में लौह अयस्क बाक्साइट और अन्य खनिजों के अतिरिक्त केसोटाराइट, कोलबाइट टैटलाइट से बने बहुखनजीय संद्र का पता चला है। इस में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ मैदान के पूर्वी तथा दक्षिणी दुर्गम पहाड़ी भू-भाग जो सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, विशेष महत्व के हैं। यदि इस भू-भाग को बरोयता के आधार पर भवित्वीय सर्वेक्षण किया जाता है, तो यह हमारे ग्रौथोगिक विकास की गति देने में सहायक होने के साथ-साथ इस आदिवासी बहुल क्षेत्र का ब्रूत गति से विकास करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

(ii) RELIEF MEASURES FOR FLOOD-AFFECTED PEOPLE OF GORAKHPUR DISTRICT OF U.P. AND CONSTRUCTION OF PROPOSED DAMS TO CONTROL FLOODS.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : विभिन्न देश के विभिन्न भागों में भयंकर बाढ़ की हित्रति व्याप्त है तथा जन-धन की भीषण अस्ति हुई है किन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राष्ट्री, रोहिन, बाचरा और आमी नदियों की बाढ़ के कारण बहां की जनता को

बोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। फसलें लगभग नष्ट हो चुकी हैं तथा प्रत्येक मकान अस्तिग्रस्त हो गये हैं। कई गांव जैसे रोहिंगा और बंजरहा राष्ट्री नदी के काटाथ के कारण कट कर नहीं में गिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन गांवों के लोगों को किसी नये स्थान पर बसाने के लिये सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिये और बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ खाद्यान्न एवं प्रन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये। याथ ही बाढ़ से प्रभावित झेलों के छात्रों की फीस माफ कर देनी चाहिये तथा उक्त झेलों में हर प्रकार की वसूली बंद होनी चाहिये और किसानों का लगान माफ कर दिया जाना चाहिये। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उक्त नदियों की बाढ़ की विभीषिका का नियंत्रित करने के लिये एक नियोजित प्रभावी कार्यक्रम बनाये ताकि लोगों को इस महान संकट से बचाया जा सके। प्रस्तावित बाधों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा दिया जाना अति आवश्यक है :

(iii) NEED FOR ENHANCING RATES OF POST-MATRICULATION SCHOLARSHIPS TO S.C. AND S.T. STUDENTS.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): Mr. Deputy Speaker, Sir, under Rule 377 I want to raise the following matter of urgent public importance.

Post-matric scholarships are awarded to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students at rates approved by Government of India. Different rates are prescribed for students of different groups as indicated in the scheme of Post-matric scholarship prepared by Government of India.

In the scheme it has been provided that Rs. 70/- p.m. for boys and Rs. 80/- p.m. for girls will be given for general courses upto graduate level. Over and above, the rate prescribed by Government of India, the State Government of Orissa are